



NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 86 /NCRES/20

Date : 9.5.2020

डा0 एम. राघवैया जी
महामंत्री, एन.एफ.आई.आर.
नई दिल्ली

विषय :- Covid-19 महामारी के समय "संघ" द्वारा कर्मचारी एवं जनहित में किये गये कार्य एवं रेलवे में खर्च कम करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्र संख्या NFIR/Covid-19/2020 दिनांक 21.4.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि कोविड-19 के मार्च 2020 में व्यापक रूप से फैलने की आशंका को देखते हुये भारत सरकार ने पूरे देश में लाक डाऊन एवं रेलवे में पैसेन्जर ट्रेन को बन्द करने का फैसला किया है परन्तु आवश्यक वस्तुओं को देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुँचाने के लिये गुड्स/पार्सल ट्रेनों का संचालन पूर्व की भांति जारी रखा गया है।

इस प्रकार जहाँ देश को हर नागरिक को संक्रमण से बचाव हेतु घर पर रहने का निर्देश दिया गया वहीं रेल कर्मचारियों को गुड्स/पार्सल ट्रेन के संचालन हेतु प्रतिदिन संक्रमण के बीच नौकरी करने को बाध्य होना पड़ा।

जहाँ शुरुआत में प्रशासन सैनिटाइजर, मास्क एवं साबुन उपलब्ध नहीं करा पा रहा था तब NCRES की विभिन्न शाखाओं द्वारा सैनिटाइजर, साबुन एवं मास्क का वितरण किया गया। इसके पश्चात् सर्वप्रथम लोको पायलटो के ब्रेथ एनीलाइजर एवं बायोमेट्रिक अटेन्डेन्स से संक्रमण के खतरे एवं NCRES द्वारा झांसी, आगरा एवं प्रयागराज मंडलो में विरोध को देखते हुये अधिकारियों एवं महाप्रबंधक से वार्ता की गई जिसके पश्चात् नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में बायोमेट्रिक अटेन्डेन्स एवं ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट बंद कर दिया गया।

इसके पश्चात् झांसी वर्कशाप एवं कानपुर शेडो से कर्मचारियों की तरफ से NCRES के पास शिकायते आई कि ऐसी जगहो पर जहां अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं वहाँ संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुये संस्थान को बंद किया जाय। इस सम्बन्ध में NCRES की तरफ से महाप्रबंधक को पत्र लिखकर वर्कशाप को बंद करने का अनुरोध किया गया जिसके बाद वर्कशाप को बंद कर दिया गया।

जहाँ प्रयागराज मण्डल में मुख्य रूप से मण्डल मंत्री गोविन्द सिंह, अखिलेश सिंह राठौर, आलोक सहगल, ए. के. पोद्दार, सत्यम गुप्ता आदि ने प्रयागराज में सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया एवं उन्हें डिटाल साबुन, सेनेटाइजर एवं मास्क वितरित किये, वहीं कानपुर में मण्डल अध्यक्ष मान सिंह एवं सिराज, तुफैल द्वारा NCRES के स्टीकर लगी बोतलों में सेनेटाइजर भरकर वितरित किया गया एवं मास्क बांटे गये।

वहीं आगरा मण्डल के मंडल मंत्री ए. के. दधीच के नेतृत्व में शाखा सचिव हरि ओम भारद्वाज आदि ने लोको लाबी पर लोको पायलटों को सेनेटाइजर एवं मास्क वितरित किया एवं सचिव उत्तम कुमार ने गार्ड लाबी पर लिक्विड सोप, हैण्ड ग्लब्स, सेनेटाइजर वितरित किये। इसके अतिरिक्त मंडल अध्यक्ष अक्षय कान्त, के. के. शर्मा एवं विजेन्द्र सिंह ने रोज 500 पैकेट भोजन का वितरण रेलवे कालोनी, रेलवे स्टेशन के आस-पास रह रहे गरीब मजदूरों एवं जरूरत मंदों को बांटा।

इसी प्रकार झांसी में झांसी मण्डल के मण्डल सचिव श्री वी. जी. गौतम, भानु प्रताप सिंह चंदेल ने झांसी में एवं झांसी मण्डल के मण्डल अध्यक्ष राम कुमार के नेतृत्व में समस्त शाखाओं ने कर्मचारियों को सेनेटाइजर, मास्क, हैण्ड ग्लब्स, साबुन आदि वितरित किये। इसके अतिरिक्त मंडल मंत्री एवं मण्डल अध्यक्ष ने पी.एम. रिलीफ फण्ड में 5000-5000 रुपये का योगदान दिया जिससे प्रेरित होकर समस्त शाखा पदाधिकारियों ने रिलीफ फण्ड में यथाशक्ति योगदान किया।

इसी प्रकार रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के विपरीत कई विभागों में कर्मचारियों की उपस्थित 33% से काफी अधिक रखी गई थी। NCRES ने सभी जगह रेलवे बोर्ड के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया।

NCRES के झांसी, आगरा एवं प्रयागराज मण्डलों में महामंत्री के दिशा-निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया जो सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखने हेतु सभी विभागों के कर्मचारियों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाने एवं उनके बीच जरूरी सामानों का वितरण करने का कार्य कर रही है। इसी के साथ NCRES, सामाजिक दायित्वों का पालन करते हुये गरीबों एवं असहाय लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था कर रही है।

यह भी अवगत कराना है कि NCRES के पदाधिकारियों ने PM Care Fund एवं मंडल स्तर पर बनी रिलीफ फण्डों में यथाशक्ति योगदान दिया जिससे गरीबों में जरूरी सामान वितरित किया जा सके।

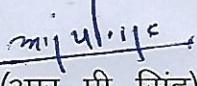
NCRES की मांग पर ही रेलवे हास्पिटल में एक कोरोना वार्ड रेलवे बोर्ड से दिशा-निर्देश के पूर्व ही बना दिया गया एवं मरीजों की हर दिक्कत को दूर करने का प्रयास किया गया।

खर्च में कटौती के बारे में मांगे गये सुझावों के बारे में NCRES का मत है कि हमें अपने आय के संसाधनों को बढ़ाना होगा इसमें से मुख्यतः -

- (1) रेलवे स्टेशनों के आस-पास एवं अन्य प्राईम जगहों को कामर्शियल कार्य हेतु किराये पर देना।
- (2) रेलवे में दी जा रही सभी प्रकार की सब्सिडी को खत्म करना।
- (3) रेलवे के किराये में 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी।
- (4) विदेशों से आयात किये जाने वाले वैगन इंजनों के बजाय रेल कारखानों में उनका कम कीमत पर निर्माण कराना।
- (5) एयर कंडीशन पार्सल ट्रेनों का संचालन से देश को ट्रान्सपोर्ट का एक नया तीव्र गति एवं अति सुरक्षित साधन देना।

NCRES का इस Covid-19 के संकट के समय मत है कि जो रेलकर्मियों राष्ट्रीय आपदा में राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं उनके वेतन, वेतन वृद्धि, डी.ए. आदि में कटौती या पेंशन आदि में कटौती नहीं करना चाहिये। इससे उनमें निराशा आयेगी क्योंकि उन्हें पहले से 7th CPC एवं अन्य मांगों के पूरा न होने से निराशा है। इसी के साथ NCRES का मत है कि यदि भारतीय रेल अपनी आय बढ़ाने के लिये यदि रेलवे में NPS को खत्म कर दे तो NPS का पूरा फंड सरकार के खाते में आ जायेगा एवं तुरन्त उन्हें 14 प्रतिशत का अंशदान भी नहीं देना पड़ेगा।

यहाँ यह कहना भी महत्वपूर्ण होगा कि कोरोना महामारी के पूर्व ही रेलवे में तमाम तरह के भुगतान को लम्बित रखा जा रहा था। ऐसे में कोरोना का कर्मचारियों की मांगों को खत्म करने का साधन न बनने दिया जाय।


(आर. पी. सिंह)
महामंत्री